

मुख्यमंत्री भजनलाल आज वंदे गंगा जल संरक्षण आंदोलन का शुभारंभ करेंगे

वे जमवारामगढ़ में वृक्षारोपण व श्रमदान, केशोरायपाटन में जल पूजन व भरतपुर में गंगा मंदिर में विशेष पूजा करेंगे

जयपुर, 4 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशभर में “वंदे गंगा जल संरक्षण” जन अभियान की महत्वपूर्ण पहल की है। विश्व पर्यावरण दिवस एवं गंगा दशहरा (5 जून) के शुभ संयोग पर शुरू होने जा रहे इस अभियान के अंतर्गत, 20 जून तक विभिन्न विभागों द्वारा प्रदेशभर में जल संरक्षण के व्यापक कार्य किए जाएंगे। इस अभियान के सफल संचालन के लिए प्रदेश के 41 जिलों में मंत्रियों की नियोजित किया गया है।

अभियान के पहले दिन 5 जून को प्रदेशभर में विभिन्न विभागों द्वारा नर्सरियों में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम, तुलसी पौध वितरण, प्लास्टिक का उपयोग कम करने की शपथ, श्रमदान, जल स्रोतों की साफ-सफाई व मरम्मत, वंदे गंगा कलश यात्रा, नदी-बाँध-सरोवर का पूजन एवं हरियालो राजस्थान के अंतर्गत पौधरोपण की तैयारी के साथ-साथ कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत कार्यों का अवलोकन एवं स्वीकृति जैसे प्रमुख कार्य किए जाएंगे।

विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री जयपुर के जमवारामगढ़ में वृक्षारोपण करेंगे। वहीं, मोरी के निकट, रामगढ़ बाँध पर श्रमदान करेंगे। उसके बाद वे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

(आरआईसी) में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करेंगे।

कार्यक्रम के बाद, मुख्यमंत्री बूंदी के लिए रवाना होंगे, जहां वे केशोरायपाटन में मुख्यमंत्री 'वंदे गंगा' जल पूजन, चुनरी महोत्सव एवं कलश पूजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और समारोह में जल स्वावलंबन अभियान

■ **अभियान के पहले दिन नर्सरियों में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम, तुलसी पौधा वितरण, प्लास्टिक उपयोग कम करने की शपथ, श्रमदान, जल स्रोतों की सफाई, वंदे गंगा कलश यात्रा, नदी-सरोवर-बाँध पूजन तथा पौधारोपण के कार्यक्रम होंगे।**

सार्वजनिक स्थानों पर वंदे गंगा जल सेवा, जल परीक्षण अभियान, जलाशयों से गाद निकालना एवं पशु-पक्षियों के लिए पीने के साफ पानी की व्यवस्था के लिए शिला-न्यास करेंगे। मुख्यमंत्री केशवराय भगवान मंदिर में पूजा-अर्चना भी करेंगे। उसके बाद शाम को भरतपुर पहुंचेंगे, जहां वे गंगा मंदिर में विशेष पूजा और सुजानगंगा में दीपदान करेंगे। निर्जला एकादशी (6 जून) के दिन रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि

भगदड़ में मारे गए लोगों को 10 लाख रु. की सहायता घोषित

बेंगलुरु, 04 जून। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर बुधवार को हुई भगदड़ में 11 लोगों के मरने की पुष्टि की है। हादसे में 33 अन्य घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल जीत के जश्न के लिए भारी भीड़ उमड़ी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया और मृतकों में से प्रत्येक के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की। सिद्धारमैया ने यहां कहा, किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। न तो क्रिकेट एसोसिएशन और न ही सरकार ने इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद की थी। स्टेडियम में केवल 35,000 लोगों की क्षमता है, लेकिन दो से तीन लाख से अधिक प्रशंसक आए।

प्रदेशवासी पर्यावरण अभियानों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल ने पर्यावरण दिवस व गंगा दशहरा पर प्रदेशवासियों के नाम संदेश दिया।**

जो के प्रसिद्ध दोहे 'रहिमन पानी राखिए...बिन पानी सब सुन.....' का उल्लेख करते हुए कहा कि 5 जून को हम हर वर्ष की तरह विश्व पर्यावरण दिवस मनाते जा रहे हैं।

संयोग से इस दिन गंगा दशहरा भी है और इसके अगले दिन निर्जला एकादशी है।

उन्होंने कहा कि यह संयोग हम सभी को पानी की महत्ता की याद दिला

कर जल संरक्षण पर विशेष रूप से ध्यान देने की ओर इशारा कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'वंदे गंगा' जल संरक्षण जन अभियान तथा 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान प्रदेशवासियों के अपने अभियान हैं, इनमें सहभागिता निभाते हुए गंगा दशमी के दिन अपने आसपास के जलस्रोत, नदियों, जलधाराओं, तालाबों की पूजा-अर्चना करें।

साथ ही, बावडियों, तालाबों, कुंओं, बांधों, नदियों के संरक्षण एवं सफाई आदि में बढ़-चढ़ कर योगदान दें। शर्मा ने कहा कि इस वर्षा काल में 10 करोड़ पौधे लगाकर हरित राजस्थान अभियान को गति देकर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं।

छः जून को प्र.मंत्री चिनाब रेलवे...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
जवाब माना जाता है।

यह पुल यूएसबीआरएल परियोजना का केन्द्र है, यह 272 किमी लंबा रेल कोरिडोर दुनिया के भूगर्भीय दृष्टि से सबसे जटिल क्षेत्रों में से एक से होकर गुजरता है। इस परियोजना में 943 से अधिक पुल और 36 प्रमुख सुरंगें हैं, जिनमें भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग (टी-50) शामिल है जो 12.77 किमी लंबी है। यह 42,000 करोड़ की इस परियोजना का लक्ष्य पूरे साल, तेज और विश्वसनीय तरीके से कश्मीर को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ रखना है।

यह कनैक्टिविटी इससे ज्यादा बेहतर समय पर नहीं आ सकती थी। अप्रैल में पहलगाम के बैसारन घाटी में हुए आतंकवादी हमले में 25 पर्यटकों सहित 26 लोग मारे गए, जिससे इस साल की रिकॉर्ड तोड़ने वाली पर्यटक संख्या पर अचानक विराम लग गया।

कश्मीर ऐसा क्षेत्र है जो पर्यटन पर आधारित गुलामों की सुंदरता, डल झील का आकर्षण, और अमरनाथ और वैष्णो देवी इसके प्रमुख आकर्षण हैं। इस राज्य तक स्थिर और सुरक्षित पहुंच कोई विलासिता नहीं, बल्कि आवश्यकता है।

चेनाब पुल और जल्द शुरू होने वाली कटरा-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस एक मजबूत संदेश देती है:

■ **इस रेल लिंक के उद्घाटन से पहले कश्मीर में पर्यटन ज्यादा से ज्यादा ग्रीष्मऋतु तक सीमित रहता था तथा मौसम के मिजाज़ पर निर्भर था। अब इस लिंक के बाद पर्यटन साल भर चलने वाली गतिविधि बनेगी तथा कश्मीर के उत्पाद, जैसे, सेब एक दिन में दिल्ली के मार्केट में पहुंच सकेंगे, बिकने के लिए।**

■ **भारत सरकार का नारा, “जनता को जोड़ो, क्षेत्र को खोलो” तथा “विकास को आने दो” , के लिए यह “टैस्ट केस” है।**

विकास को हिंसा के द्वारा रोक नहीं जा सकता। वंदे भारत ट्रेन को खासतौर पर इस क्षेत्र की जलवायु के अनुसार तैयार किया गया है – इसमें हीटिंग पैड और सेंसर लगे हैं ताकि सर्दियों में बर्तन जमने से बचा जा सके। इससे सर्दियों में जब यह क्षेत्र शेष विश्व से कट जाता है, यात्रा तेज़, आरामदायक और सुरक्षित होगी।

अब तक सीमित हवाई संपर्क और मौसम-आधारित सड़कों के कारण पर्यटन मौसम पर निर्भर और अनिश्चित रहता था।

लेकिन अब प्रत्यक्ष रेल संपर्क से पर्यटक आसानी से श्रीनगर पहुंच सकेंगे, जिससे मुख्यधारा के पर्यटन के साथ-साथ धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे पूरे साल पर्यटन को स्थिरता मिल सकती है।

बेहतर संपर्क केवल पर्यटक ही

नहीं लाता, बल्कि यह रोजगार, आय और आशा भी लाता है। स्थानीय व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, होटल मालिक और हस्तशिल्प कारीगर इससे भारी लाभ कमा सकते हैं। यह रेल लाइन कश्मीरी सेब उत्पादकों के लिए भी वरदान साबित होगी – अब सेब एक दिन में ही दिल्ली के बाजारों तक पहुंच सकेंगे, साथ ही घाटी को आवश्यक वस्तुओं और दवाइयों की आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी।

पिछले दो वर्षों में कश्मीर में पर्यटन ने फिर से गति पकड़ी थी, और अप्रैल की त्रासदी से पहले रिकॉर्ड पर्यटक आ रहे थे। इस गति को धमने नहीं देना चाहिए।

पुल और ट्रेन सेवा सरकार की "आतंकवाद के बदले विकास" नीति को मूर्त रूप देते हैं। इससे यह संदेश जाता है: लोगों को जोड़ो, क्षेत्र को

खोलो और विकास को अंदर आने दो। चेनाब पुल सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि संघर्ष और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। यह कश्मीरियों और संभावित पर्यटकों दोनों को यह विश्वास दिलाता है कि सामान्य स्थिति कोई सपना नहीं, बल्कि एक उभरती हुई वास्तविकता है। यह एक ऐसा कदम है जो सुनिश्चित करता है कि घाटी के भविष्य को भय से परिभाषित न किया जाए।

‘अमेरिका की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
पीएम मोदी और विदेश मंत्री इस मुद्दे पर पूरी तरह चुप हैं, जिसके चलते भारतीय छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि विदेश मंत्रालय के अनुसार, साल 2024 में लगभग 3,37,630 भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए।

उन्होंने बताया कि अमेरिकी कॉलेजों में जितने विदेशी छात्र हैं, उनमें से एक-तिहाई भारत से हैं। इसका मतलब है कि करीब साढ़े तीन लाख भारतीय परिवारों ने अपनी मेहनत की कमाई या लोन लेकर अपने बच्चों की अमेरिका में पढ़ाई के लिए खर्च किया है।

बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रहे।" पत्र आगे कहता है कि रिकॉर्ड पर आ चुके मामले की गंभीरता के बावजूद, अब तक न तो कोई एफआईआर दर्ज हुई है और न ही अधिकृत जाबो या पंचनामे की कार्यवाही की गई है। यह निष्क्रियता जाँच प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर गंभीर प्रश्न खड़े कर रही है। बीएएल ने अपने पत्र में 1991 के के. वी.रास्वामी बनाम भारतीय संघ केस में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया था कि न्यायाधीश भी पीसी एक्ट के तहत "लोक सेवक" हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

बीएएल ने यह भी आग्रह किया है कि 3 मई को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को सौंपी गई इन-हाउस समिति की रिपोर्ट, जिसमें न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोप बताए गए हैं, सार्वजनिक की जाए। 8 मई को सुप्रीम कोर्ट की प्रेस विज्ञापन में बताया गया था कि यह रिपोर्ट और न्यायमूर्ति वर्मा का 6 मई का उत्तर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया गया है।

बीएल ने जस्टिस वर्मा के अभियोजन की शुरुआत के लिए सीजेआई की स्वीकृति की माँग करते हुये, इस बात को रेखांकित किया है कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं तथा संस्थागत जवाबदेही जरूरी है।

इधर उच्चस्तरीय सरकारी सूत्रों ने बताया कि केन्द्र सरकार डेच न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद उन पर ये आरोप लगे हैं।

किसी वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही भारत के संवैधानिक ढांचे की सबसे दुर्लभ और संवेदनशील प्रक्रियाओं में से एक है।

सूत्रों के अनुसार, संसद के आगामी सत्र में उन्हें पद से हटाने (महाभियोग) के लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

संसदीय कार्य मंत्री विरेन रिजिजू इस प्रस्ताव को

■ **दूसरी ओर चर्चाओं के अनुसार, सरकार आगामी सत्र में न्यायाधीश वर्मा के खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव संसद में लाने की तैयारी कर रही हैं तथा संसदीय मामलों के मंत्री विपक्ष के नेताओं से इस संबंध में बातचीत कर रहे हैं। विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल भी इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह से मिले और फिर दोनों प्र.मंत्री से मिलने गये, बुधवार रात को। राज्यसभा के नेता जे.पी. नड्डा भी गृह मंत्री शाह से मिले, फिर दोनों सभापति, जगदीप धनखड़ से मिलने गये।**

सदन में लाने से पहले सभी राजनीतिक दलों से

विचार-विमर्श करेंगे।

सूत्रों का कहना है कि चूंकि न्यायाधीश को हटाने के लिए संविधान में एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, इसलिए सभी दलों की सहमति अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।

बुधवार को कई महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया गया, जिनमें संभवतः इस प्रस्ताव को लेकर रणनीति तैयार की गई।

सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके थोड़ी देर बाद शाह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की।

थोड़ी देर बाद राज्यसभा में पार्टी के नेता जे.पी. नड्डा ने शाह से मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेताओं ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। पूर्व में दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यरत रहे जस्टिस वर्मा उस समय विवादों में आए जब दिल्ली के 30 तुगलक क्रैसेंट स्थित उनके सरकारी आवास पर लगी आग के बाद, कथित रूप से बड़ी मात्रा में बेहिसाब अधजली नकदी बरामद हुई।

बैंगलूरु में आईपीएल की जीत के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जाना भी शामिल है। लेकिन, हम युवा एवं उत्साही भीड़ पर लाठियों का प्रयोग भी नहीं कर सकते थे।"

आरसीबी टीम ने मंगलवार को ट्राफी जीती और टीम बुधवार को दोपहर बाद एचएल हवाई अड्डे पर उतरी थी तथा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से भेंट करने के लिए विधानसभा की ओर रवाना हुई थी।

राज्य के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने हवाई अड्डे पर रजत पाटीदार के नेतृत्व वाली इस टीम का स्वागत किया था। इसी बीच, ऑनलाइन

सर्कुलेट हो रहे विजुअल्स में दिखाई दिया कि पुलिस के जवान घायलों तथा बेहोश लोगों को पड़ोस के अस्पताल ले जा रहे हैं। चित्रस्वामी स्टेडियम के नजदीक स्थित क्यूबन पार्क मेट्रो स्टेशन के प्रवेश एवं निकासी द्वारा बंद कर दिये गये थे।

कर्नाटक के मुख्य विपक्षी दल, भाजपा ने इस दुःखद घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने अपने अधिकृत "एक्स" हैंडल पर ट्वीट किया कि "सात लोग मर गये। कांग्रेस सरकार की गैर जिम्मेदारी के कारण हुई भगदड़ के बाद, अन्य बहुत से लोग जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भीड़-

नियंत्रण के कोई उपाय नहीं किये गये। मूलभूत व्यवस्थाएँ तक नहीं थीं। अव्यवस्था ही अव्यवस्था थी। जहाँ निर्दोष लोग मर रहे थे, वहीं मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री क्रिकेटर्स के साथ रेलों की शूटिंग तथा लाइमलाइट में आने में व्यस्त थे। फोटो खिंचवाने के अवसरों की ताक में रहने वाली, इस कांग्रेस सरकार को धिक्कार है। यह एक आपराधिक लापरवाही है। कांग्रेस सरकार के हाथ खून में रंगे हुये हैं।"

इस दुःखद घटना की विस्तृत जानकारी तथा उसके बाद उठाये गये कदमों की रिपोर्टों की प्रतीक्षा है।

भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रभारियों की नियुक्ति वेणुगोपाल ने की है या वे सीधे उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं तथा उनसे ही निर्देश प्राप्त करते हैं।

इनमें जयराम रमेश, दीपा दास मुंशी, अविनाश पांडे, हरीश चौधरी, देवेन्द्र यादव कई अन्य नेता शामिल हैं। पार्टी में आम धारणा यह बन गई है कि अगर पार्टी में किसी को टिकना है तो यह वेणुगोपाल के आशीर्वाद से ही हो सकता है, जो राहुल गांधी के "आंख, कान और सब कुछ" है।

दिलचस्प बात यह है कि अविनाश पांडे को प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था, लेकिन कुछ दिन बाद, उन्होंने खेमा बदल लिया और अब वे के सी वेणुगोपाल को ही रिपोर्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव में मांत्र डेढ़ साल बचा है और पार्टी का संगठन बिखरा हुआ है।

राजस्थान प्रभारी रंधावा, जिन्हें हटाया जाना था, वेणुगोपाल के खेमे में शामिल हो गये, और इसलिये उन्हें बचा दिया गया। अब रंधावा भी उसी गुट का हिस्सा हैं जो वेणुगोपाल को रिपोर्ट करता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थक-हार कर, वेणुगोपाल के जरिए ही पार्टी में वापसी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले गांधी परिवार और सोनिया गांधी के खिलाफ बगवात की

■ **वस्तुस्थिति यह है कि एआईसीसी के अधिकांश पदाधिकारी व राज्यों के प्रभारी, वर्तमान में वेणुगोपाल के प्रति वफादारी रखते हैं, क्योंकि, वे सब वेणुगोपाल द्वारा नियुक्त किये गये हैं या उनकी जवाबदेही वेणुगोपाल से हैं तथा वेणुगोपाल से निर्देश लेकर ही काम करते हैं। इनमें प्रमुख हैं, जयराम रमेश, दीपा दास मुंशी, अविनाश पाण्डेय, हरीश चौधरी, देवेन्द्र यादव आदि।**

■ **बघेल जो पंजाब के प्रभारी हैं, भी इसी क्रम में, वेणुगोपाल के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अतः वे पंजाब के किसी भी मुद्दे पर, कोई "स्टैंड" नहीं लेते, केवल वो ही करते हैं, जो वेणुगोपाल चाहते हैं। राजस्थान के प्रभारी रंधावा, पंजाब के वरिष्ठ नेतागण, जैसे राजा वडिंग, प्रताप सिंह बाजवा आदि भी वेणुगोपाल के खेमे में हैं और उन्हें वेणुगोपाल का संरक्षण प्राप्त है।**

■ **हालांकि, ये नेता आम आदमी पार्टी व भाजपा के हाथ में कठपुतली हैं तथा कांग्रेस संगठन पंजाब में धरातल में धंसा जा रहा है। पंजाब के प्रभारी बघेल कुछ भी हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं दिखा रहे, केवल वेणुगोपाल की ओर देख रहे हैं, उनका आदेश जानने के लिए।**

थी, इसलिए अब गहलोत की वापसी के लिये राहुल गांधी को मनाना वेणुगोपाल के लिए भी कठिन हो रहा है।

अंबिका सोनी भी गहलोत का

समर्थन कर रही है, लेकिन वे भी कोई खास असर नहीं डाल पा रही हैं, भले ही सोनिया गांधी उनकी बातों को तवज्जो देती हैं।

एआईसीसी में कुछ नेतागण तो

वेणुगोपाल का हुकुम मानने के लिये इसलिये बाध्य हैं कि उन्हें पार्टी में बने रहना है, जबकि कुछ लोग ऐसा इसलिये करते हैं क्योंकि उन्हें पार्टी में आगे बढ़ना है तथा अपने लक्ष्य एवं आकांक्षाएं हासिल करनी हैं।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा "अगर भूपेश बघेल जैसा प्रियंका गांधी का वफादार नेता भी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए खेमे बदल सकता है, तो यह इस बात का पर्याप्त संकेत है कि एआईसीसी के परिसर में किस तरीके की सत्ता की राजनीति चल रही है।"

समझा जाता है कि बघेल की ओबीसी पहचान, पूर्व मुख्यमंत्री होने और एक 'प्रैजेटेबल चेहरा' होने की वजह से वे राहुल गांधी की सोच के मुताबिक नेताओं की उस सूची के लिये उपयुक्त हैं, जिन्हें पदोन्नत किया जाना चाहिये।

जहाँ तक उनके खिलाफ मुकदमे होने तथा एम्फोसैमेन्ट डायरेक्ट्रेट (ईडी) द्वारा उनके पास सम्पन्न भेजे जाने का प्रश्न है, ये बातें कोई खास महत्व नहीं रखतीं, क्योंकि ईडी ने गांधी परिवार की भी सम्पन्न भेजे हैं तथा पृष्ठताछ की है।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अब मैदान सबके लिये बराबर एवं समान है।